सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 260 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 03 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

गरीबों का आशियाना उजाड़ने वाले माफी के लायक नहीं : सांसद बृजमोहन

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नकटी गांव में हुई बेदखली एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई है। नई दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नकटी के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, जो भी लोग रात के अंधेरे मे गरीबों के आशियाने में बरसात में तोड़-फोड़ की है, वो माफ करने लायक नहीं हैं। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सीए फाउंडेशन के नतीजे घोषित, साक्षी जैन ने किया टॉप

नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 14 से 20 मई 2026 के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 20.09 फीसदी रहा, जबकि लगभग 18,124 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। साक्षी जैन ने 400 में से 371 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है। सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में नासिक की साक्षी जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 में से 371 अंक (92.75 फीसदी) हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें देशभर के अभ्यर्थियों में शीर्ष स्थान दिलाया।

ईपीएफ में 1800 से अधिक का अंशदान अब स्वैच्छिक

नई दिल्ली। वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी अंशदान ईपीएफ में करना होता था और कंपनी भी इतना ही अंशदान ईपीएफ में करती थी, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के तहत नए प्रावधान अधिसूचित कर दिए हैं। इस प्रावधान के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर किए जाने वाले अंशदान को स्वैच्छिक बना दिया है। यानी 15,000 की वेतन सीमा पर निर्धारित 1800 से अधिक का ईपीएफ अंशदान अब अनिवार्य नहीं होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को लिखा पत्र, यात्रा पर पांच संकल्प लेने की अपील

नईदिल्ली। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन हर शिवभक्त के लिए सौभाग्य का विषय हैं और यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने, पर्यावरण की रक्षा करने और स्थानीय लोगों का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने पांच महत्वपूर्ण संकल्प लेने का भी आग्रह किया, ताकि यह यात्रा आस्था के साथ-साथ सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी दे सके।

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा के साथ ही बाबा अमरनाथ के दर्शन का पावन क्रम शुरू हो जाता है और देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ धाम की यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा देने के साथ-साथ भारत की विविधता में एकता की भावना को भी मजबूत करती है।

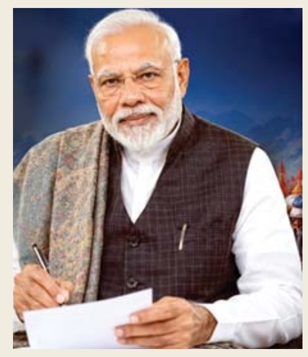

प्रधानमंत्री मोदी ने की इन संकल्पों के साथ यात्रा करने की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं से पांच महत्वपूर्ण संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने और किसी भी तरह की गंदगी न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें तथा बारिश, ठंड और कठिन मौसम को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें। इसके अलावा उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश देते हुए आग्रह किया कि यात्रा पर होने वाले कुल खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा जम्मू-कश्मीर के स्थानीय उत्पादों की खरीद पर खर्च करें, ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत हो सके। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधा लगाने और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का भी आह्वान किया।

सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मियों को अब ई-कोष से मिलेगा आसान लोन

छत्तीसगढ़ सरकार शॉर्ट टर्म क्रेडिट शुरू करने का लिया निर्णय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए अल्पावधि ऋण (शॉर्ट टर्म क्रेडिट) सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी आकस्मिक जरूरतों के समय डिजिटल माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया राज्य शासन की ई-कोष (द्ग-न्नशद्मद्ध) प्रणाली से जुड़ी होगी, जिससे ऋण वितरण तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक जरूरतों या अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अनौपचारिक या महंगे कर्ज के विकल्पों पर निर्भर न रहना पड़े।

एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल सत्यापन और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृत कर राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की मासिक किस्तें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे वेतन से काटी जाएंगी। सरकार के अनुसार, आवेदन से पहले कर्मचारियों को ब्याज दर, ईएमआई, सेवा शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट (चस्न्नस्) जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनदेन

वित्त विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। इसके तहत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा और सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से शासकीय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें जरूरत के समय बिना अनावश्यक औपचारिकताओं के त्वरित वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : दुर्ग, बिलासपुर व बस्तर संभाग में की एल्डरमैनों की नियुक्ति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर और सरगुजा संभाग के बाद राज्य सरकार ने बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मनोनीत पार्षदों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है।

बस्तर संभाग में 63, बिलासपुर संभाग में 197 और दुर्ग संभाग में 146 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। रायपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों में 254 एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई थी। इन नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश के सभी पांचों संभागों के नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्तियां छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं।

साय केबिनेट की बैठक 8 जुलाई को

रायपुर। राज्य मंत्रिपरिषद् (केबिनेट) की बैठक बुधवार, 08 जुलाई को सुबह 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास व जनहित को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

ई-रिक्शा को बीच सड़क रोकने वाला मोबाइल एप बैन

नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों को इन दिनों एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर चलते-चलते अचानक ई-रिक्शा बंद हो जाते हैं और दोबारा स्टार्ट नहीं होते। जांच में सामने आया है कि कोई मैकेनिकल खराबी या बैटरी डिस्चार्ज होना इसकी वजह नहीं है, बल्कि BAT-BMS नाम का एक स्मार्टफोन एप है। शरारती तत्व और सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट बनाने वाले लोग इस एप की मदद से दूर बैठे ही ई-रिक्शा को बंद कर रहे हैं। 3 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि 'BAT-BMS' समेत दो मोबाइल एप्लिकेशन्स को एप स्टोर्स से हटवा दिया है। CII साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने इसकी पुष्टि की है।

बेटे का गला घोंटकर मां और भाई ने ले ली जान, हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए फांसी पर लटकाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपने ही सगे बेटे की हत्या कर दी। इस वारदात में मृतक का सगा भाई भी शामिल था। पुलिस ने हत्या के मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुरुद थाना क्षेत्र के बिरेझर चौकी अंतर्गत ग्राम गोजी में 29 जून को 23 वर्षीय नरसिंग साहू का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला था। सूचना मिलने पर बिरेझर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद शव को फांसी के फंदे से लटकाया गया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

जांच के दौरान मृतक के भाई 22 वर्षीय नरेश साहू और मां 60 वर्षीय कमला बाई साहू से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि मृतक शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। पैसे नहीं मिलने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। इससे आक्रोशित दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरीः पुलिस का बड़ा खुलासा व्हाट्सएप पर चोरी को लेकर होती थी बातचीत

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के मोबाइल से बेहद पुख्ता साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। कई आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में रकम पार करने और उसके बंटवारे को लेकर बातचीत मिली है। पुलिस ने इसे विवेचना में मजबूत साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है।

सूत्रों के मुताबिक, गणना के समय पर अधिक बातचीत नहीं हो पाती थी, लिहाजा उस दौरान आरोपी व्हाट्सएप पर एक-दूसरे को मैसेज भेजते थे। इसके जरिये कब और कैसे रकम पार करनी है, यह तय किया जाता था। बाद में एक जगह मिलकर उसका बंटवारा करते थे। बंटवारे को लेकर भी चैट मिली है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी करवा रही है। कई आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट डिलीट करने के भी साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की जांच में जितने तथ्यों की जरूरत थी, उतने मिल गए हैं। पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल खंगाले तो उनमें कई फोटो और वीडियो मिले।

तीन बच्चों को मारकर मां ने दी जान

मानसा। पंजाब के मनसा शहर के वार्ड नंबर-3 स्थित इच्छा पूर्वक गुरुद्वारा साहिब के पास किराये के मकान में रहने वाली एक विधवा मजदूर महिला ने कथित तौर पर पहले अपने तीन बच्चों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और फिर खुद फंदा लगाकर जान दे दी। घटना में चारों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आर्थिक तंगी को घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। मृतकों की पहचान संदीप कौर (35), उसकी 12 वर्षीय बेटी कालो, सात वर्षीय बेटी मोटो और डेढ़ वर्षीय बेटे विश्वास के रूप में हुई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा देर शाम उस समय हुआ जब महिला का एक रिश्तेदार घर पहुंचा।

छत्तीसगढ़ में 17 न्यायिक अधिकारियों का तबादले

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिला-सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार, जगदलपुर के प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को स्पेशल जज (NIA कोर्ट), जगदलपुर नियुक्त किया गया है। वहीं, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओमप्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बलौदाबाजार के प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बनाया गया है। बलौदाबाजार के प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा का तबादला छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी,

बिलासपुर में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर किया गया है। द्वितीय जिला-सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर रूपनारायण पात्रे को हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का सचिव बनाया गया है। सिद्धार्थ अग्रवाल को द्वितीय अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर से प्रथम अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर नियुक्त किया गया है।

किरण कुमार जांगड़े को प्रथम अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर-रामानुजगंज बनाया गया है। विनय कुमार प्रधान को एफटीसी (POCSO), रायपुर से रायपुर की एफ्टीसी कोर्ट में पदस्थ किया गया है। वहीं, डमरूधर चौहान को षष्ठम अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, रायपुर से दशम अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, रायपुर बनाया गया है। तबादला आदेश में विनिता वारनेर को प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर से बलौदाबाजार भेजा गया है। थामस एक्का को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सूरजपुर से प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर बनाया गया है। संगीता नवीन तिवारी को स्पेशल जज (NIA), जगदलपुर से प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार नियुक्त किया गया है। डॉ. मनोज कुमार प्रजापति को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर-रामानुजगंज से सारंगढ़ भेजा गया है।

अमित राठौर को द्वितीय अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़ से रायपुर स्थानांतरित किया गया है। सुमित कपूर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) पद से जिला-सत्र न्यायाधीश, रायपुर तथा अमित कुमार कोहली को छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी के एडिशनल डायरेक्टर पद से प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर-रामानुजगंज नियुक्त किया गया है।

संपादकीय

बेलगाम होता भ्रष्टाचार

सीबीआई की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलावत को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, वह नकली दवा बनाने वाले रैकेट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्वतखोरी कांड के समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया। उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह से बाड़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह-रह कर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं, जो गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूल संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया। भ्रष्ट अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार बेलगाम है। कुछ मामले तो ऐसे सामने आते हैं, जो खुले-नग्न भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं एक तरह की खुली लूट थी। इसे इससे समझा जा सकता है कि बिना जरूरत कई गुना महंगे दामों पर दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम-कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डा. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के वारे-न्यारे किए जा रहे थे, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपये में से करीब 50 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों की जेब में गए। नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाही केवल सरकारी खजाने को लूटने का काम ही नहीं कर रही है, वह आम लोगों की समस्याएं बढ़ाने का भी काम कर रही है, क्योंकि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी होता है।

“ कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह से बाड़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह-रह कर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं, जो गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूल संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया।

भारत ने सबसे बड़े ऊर्जा संकट का कैसे सामना किया

हरदीप सिंह पुरी

होर्मुज संकट का मुकाबला

जब फरवरी के अंत में होर्मुज की खाड़ी बंद हुई, तो भारत सरकार ने एक प्राथमिकता का चयन किया – हमारे देश के नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर समुदायों, को अभूतपूर्व आपूर्ति और मूल्य व्यवधानों से सुरक्षित रखना। इस प्राथमिकता के आस-पास ही अन्य प्रयास किये जाने थे। यह भावना खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की थी और यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा व्यवधान के लगभग चार महीनों तक बनी रही।

तथ्यों के पता चलने से पहले ही भारत को लेकर निर्णय किये जा रहे थे: तर्क यह था कि एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, होर्मुज के बंद होने से संभल नहीं पायेगा, जिससे होकर दुनिया का 20-30% से अधिक हाइड्रोकार्बन गुजरता है। पेट्रोल पंप में कुछ ही दिनों में तेल ख़त्म हो जाएगा, कीमतें आसमान छुएंगी (जैसे कि कई अन्य देशों में हुआ) और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज स्टॉक भरे हुए हैं, पंप खुले हैं, और भारतीय उपभोक्ता ने इस संकट के दौरान ऊर्जा के लिए दुनिया के किसी भी अन्य उपभोक्ता की तुलना में कम भुगतान किया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसे कैसे किया गया और इससे गलत आख्यानों को जवाब भी मिल जाएगा।

28 फरवरी को ईरान पर हमलों से वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण मार्ग-खंड बंद हो गया और एलपीजी आपूर्ति ने भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की, क्योंकि दुनिया में केवल अमेरिका और मध्य पूर्व ही प्रमुख एलपीजी निर्यातक हैं। भारत की लगभग 60% एलपीजी पहले मध्य पूर्व से आती थी और यह आपूर्ति तुरंत लगभग शून्य हो गई। फिर आपूर्ति और मांग, दोनों को लेकर एक युद्धकक्ष ऑपरेशन शुरू हुआ, हर कार्गो, हर रिफाइनरी, हर बॉटलिंग प्लांट की निगरानी की गयी, ताकि पूरे देश के सभी रसोईघरों में खाना पकाने के लिए आग जलती रहे।

आपूर्ति के संबंध में, 8 मार्च को एलपीजी नियंत्रण आदेश पारित किया गया, जिसके तहत सभी रिफाइनरियों को अपना एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के लिए सभी सी3-सी4 कार्बन स्ट्रीम को बदलने का निर्देश दिया गया। जो रिफाइनरी कभी कुकिंग गैस नहीं बनाती थीं, बदलाव किया गया और उत्पादन 35 टीएमटी प्रति दिन से बढ़कर 54 टीएमटी प्रति दिन हो गया। युद्ध की सर्वाधिक विभीषिका के दौरान, जब होर्मुज से कोई भी जहाज बाहर नहीं निकल रहा था, तब 12 से अधिक भारतीय एलपीजी जहाजें चुपचाप होर्मुज से बिना कोई टोल दिए निकाल दी गईं – किसी भी देश के लिए यह सबसे बड़ी संख्या थी।

कार्गो सुरक्षित किए गए तथा यानबू और फुजैरा बंदरगाहों से लाल सागर रास्ते के जरिए कार्गो जहाज-से-जहाज स्थानांतरित किये गये। अमेरिका से कार्गो को सुरक्षित करने की स्थिति में भी खाली जहाज भेजे गए, नए माल लेने के लिए जहाज हॉर्मुज के अंदर भेजे गए तथा अल्जीरिया, जापान और कनाडा जैसे कई देशों के साथ नई आपूर्ति व्यवस्था शुरू की गयी। मैंने हर उस देश के ऊर्जा मंत्री से कई बार बात की, जो एलपीजी निर्यात कर सकता था। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि खाड़ी क्षेत्र के अंदर या बाहर का हर उत्पादक, जिसके साथ हमने व्यापार किया, हमारे साथ खड़ा रहा।

हालांकि, आपूर्ति प्रयास का केवल आधा हिस्सा था, क्योंकि मांग को भी प्राथमिकता देना जरूरी था। घरों में जाने वाला रसोई गैस पूरा सुरक्षित रखा गया और इस कीमती आपूर्ति को काले बाज़ारियों से बचाने के लिए डिजिटल सत्यापन कोड अनिवार्य किया गया। हर नागरिक को उनके ज़रूरत के समय सिलेंडर मिलें, लेकिन कोई भी सिलेंडर जमा न कर सके, इसके लिए 25 दिन और 45 दिन की सीमा लगाई गई। चूँकि, वाणिज्यिक सिलेंडरों को नियंत्रित नहीं किया जाता और कोई भी खरीदार उपलब्ध पूरी आपूर्ति एक साथ खरीद सकता था, इसलिए इन्हें उद्योग संघों और राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से भेजा गया, ताकि हर किसी को पर्याप्त मिले और कोई भी जमा न कर सके। उद्योग को पाइप प्राकृतिक गैस अपनाने के लिए कहा गया, बड़े रसोईघरों और प्रतिष्ठानों को अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहाँ संभव था और घरेलू पाइप गैस और सीएनजी को बिना कटौती वाले वर्ग में रखा गया। सरकार के सभी विभागों ने मिलकर नगर निगम की शीघ्र मंजूरी के ज़रिए पाइप गैस कनेक्शनों की ओर बदलाव को संभव बनाया। कई उपभोक्ता, जिनमें प्रवासी भी शामिल थे, एजेंट से सिलेंडर खरीदते थे, जो अब डीएसी की शर्तों के कारण सिलेंडर नहीं ला पा रहे थे, इसलिए पूरे देश में 5 किलो का मुफ्त व्यापार सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, जब तक इसका इस्तेमाल लगभग दोगुना नहीं हो गया। लोगों में भय पैदा करने वाले और खराब स्थिति बताने वाले झूठी अफवाहें फैलाने लगे और झूठे वीडियो शेयर करने लगे ताकि कमी, घबराहट और अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके, जबकि सरकार हर दिन युद्धकक्ष मोड में कई क्रांतिकारी कदम उठा रही थी, ताकि देश में किसी भी जगह आपूर्ति में बाधा न आये।

इस सब के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ संकल्प था – भारतीय नागरिक को सुरक्षा दी जायेगी चाहे खजाने पर कितना भी बोझ क्यों न पड़े —रूस-यूक्रेन संघर्ष और जीवन को संकट में डालने वाली कोविड चुनौती से पैदा हुए ऊर्जा संकट के दौरान यही 'भारत की राह' रही है। फरवरी और जून के बीच, रसोई गैस के अंतरराष्ट्रीय मानक, सऊदी सी पी, में लगभग 50% की वृद्धि हुई, और फिर भी, उस आयात दर पर 1,600 से अधिक की कीमत वाला सिलेन्डर उज्ज्वला घर तक 642 में पहुँचा। मोदी सरकार हर उज्ज्वला सिलेंडर पर लगभग 900 का और हर अन्य घर के लिए जाने वाले सिलेंडर पर करीब 600 का नुकसान उठाती है, आज सभी भारतीय परिवार अपने रसोई गैस के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, स्पेन या फ्रांस के घरों की तुलना में बहुत कम भुगतान कर रहे हैं।मार्च में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 प्रति लीटर की कटौती का साहसिक निर्णय लिया गया, जिससे कीमत-वृद्धि में कमी आयी, जबकि कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गयी थी और सरकारी तेल कंपनियों ने इस तिमाही में हर दिन 500 से 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाया। इसी अवधि में, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 40% से अधिक और ब्रिटेन में करीब 20% बढ़ी, जबकि यूरोप के बड़े हिस्से में भी दहाई अंक की वृद्धि हुई, लेकिन भारत में कीमत में लगभग 7त्न की ही वृद्धि हुई।

एक और कहानी यह थी कि पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, विदेशी भंडार ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आर्थिक संभावनाएँ धुंधली हो जाएंगी। भंडार खुद जवाब देते हैं, जो लगभग 690 बिलियन डॉलर के करीब है। यह संघर्ष शुरू होने के सप्ताह में रिकॉर्ड किये गये उच्चतम दर से केवल थोडा कम है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 7.8त्न की वृद्धि दर्ज की है।

यह कहा गया कि भारत के पास केवल 8 या 9 दिन का भंडार है और उसके पास ज्यादा भंडार रखने की वास्तविक क्षमता नहीं है, यह दावा 1.5 बिलियन लोगों वाली बड़ी ऊर्जा अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को गलत रूप में समझता है। आप किसी देश को कुछ गुफाओं से नहीं चला सकते, क्योंकि जमीन के भीतर रखी गई ऊर्जा से कुछ भी कमाई नहीं होती और उसे रखने में बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है। इसके बजाय आप इसे इम्पोर्ट टर्मिनल, डिपो, पाइपलाइन, रिफाइनरी और पूरे देश में फैले स्टोरेज के सिस्टम के जरिए चलाते हैं, और आज भारत के पास 24 रिफाइनरी हैं, 47,000 किलोमीटर से ज्यादा तेल और गैस की पाइपलाइनें हैं, और 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जो प्रतिदिन करीब 8 करोड़ लोगों की सेवा करते हैं।

उस प्रणाली की वास्तविकता की जांच, महाप्रलय का भय दिखाने वाले किसी भविष्यवक्ता की स्लाइड पर दिखाए गए आंकड़े से नहीं होती। असली जांच है – आधुनिक समय के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के लगभग चार महीने गुजर जाने के बाद, क्या देश को अपने लोगों पर राशनिंग लागू करनी पड़ी, क्या ईंधन सिर्फ सम-विषम नंबर प्लेट्स के हिसाब से देना पड़ा, क्या घर में ऑफिस बनाना पड़ा या क्या हर दिन 5 बजे अपने पंप बंद करने पड़े। भारत को इनमें से कोई काम नहीं करना पड़ा। यह सब इसलिए संभव हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों में इसकी तैयारी की गई थी। हमारे कच्चे तेल के बास्केट को 27 देशों से बढ़ाकर 41 करना, हमारे आयात टर्मिनल को दुगना करना, और प्रधानमंत्री मोदी के तहत एक दशक में बनाए गए पाइपलाइन और भंडार, होर्मुज के बंद होने पर ये सभी चीजें उपयोगी साबित हुईं; यही वजह थी कि रोशनी जलती रही।

इस स्तर का संकट एक देश को उसकी असली क्षमता दिखाता है। भारत ने होर्मुज के बंद होने की बाधा पार की और देश में कहीं भी बिना किसी कमी के आपूर्ति जारी रही। इस अनुभव से सीख लेकर, हम अपनी ऊर्जा सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण करेंगे, लेकिन जब इस संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, तो एक पंक्ति मौजूद रहनी चाहिए: मानव स्मृति का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हमारे तटों तक पहुंचा, लेकिन 150 करोड़ भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे।

लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।

प्रकृति और मनुष्य के बीच भी भावनात्मक संबंध बढ़ें

पं. विजयशंकर मेहता

पेड़ भी कुछ कहना चाहते हैं। यह प्रकृति के पक्ष में बोली जाने वाली आदर्श पंक्तियां नहीं, इसके पीछे एक सच काम कर रहा है। 20 से 100 किलोहर्ट्ज पर पेड़-पौधे आवाज करते हैं और इसे दूसरे पेड़ और कुछ जानवर सुनते भी हैं। इसके वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं। जैसे शांत पलों में पेड़ कुछ गुनगुनाते हैं। उनके फूल तोड़ने पर वो आहत नहीं होते। अब धीरे-धीरे मनुष्य को चाहिए कि वो पौधों की आवाज सुने और ऐसा हो भी सकेगा। जो मनुष्य अपनी आत्मा पर बहुत अधिक टिकेंगे, आत्मा के निकट होंगे, वो पेड़-पौधों की आवाज सुन सकेंगे।

प्रकृति और मनुष्य के बीच जो भावनात्मक संबंध है, वो और बढ़ना चाहिए, वरना मनुष्य से मनुष्य के बीच का भावनात्मक संबंध तो बिगड़ेगा ही। जघन्य अपराध पहले पुरुषों के खाते में ही जाते थे। अब कुछ बहन-बेटियां भी सीमाएं लांघ रही हैं।

अपराध हुआ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान हुआ कि परिवारों में एक-दूसरे के रिश्ते पर संदेह खड़े हो गए। प्रकृति से हम जितने दूर होंगे, उतने ही हिंसात्मक, आक्रामक और निगेटिव होते जाएंगे।

चीन प्लस-वन का विकल्प बनता यूपी

डॉ. मनिष दाभाडे

किसी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक अकेला निर्णय न केवल भूगोल को, बल्कि समूची नियति को बदल देता है। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और व्यावसायिक उड़ानों का शुभारंभ निःसंदेह ऐसा ही एक क्षण है, लेकिन इसे केवल एक हवाई अड्डा कहना भूल होगी। भू-अर्थशास्त्र की दृष्टि से जेवर महज एक अवसंरचना नहीं, एक घोषणापत्र है, जो भूगोल, आर्थिक शक्ति और भू-राजनीतिक रणनीति का संगम है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो सदियों से अपनी भूबद्ध स्थिति की बेड़ियों में जकड़ा रहा, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के द्वार पर दस्तक दे रहा है।

24 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य जनसंख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, लेकिन समुद्री व्यापार मार्गों तक उसकी सीधी पहुंच नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डा उद्घाटन के अवसर पर इसी सच्चाई को रेखांकित किया कि यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की भूबद्ध बाधाओं को तोड़कर राज्य के एमएसएमई, कृषि और भारी उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। जेवर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह भू-आर्थिक सोच का संक्षिप्त सार है कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार है।

भू-अर्थशास्त्र के सिद्धांत यह स्थापित करते हैं कि किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का मार्ग उसकी भौगोलिक बनावट से होकर गुजरता है। अभी जेवर हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्री और 2.5 लाख टन कार्गो की है, जो अंततः सात करोड़ यात्री और 10 लाख टन कार्गो तक विस्तृत होगी। यह हवाई अड्डा राज्य को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़कर उसकी भूबद्ध बाधाओं को पार करने में मदद करेगा। जेवर को साधारण हवाई अड्डे से अलग करने वाली बात उसकी एरोट्रोपोलिस परिकल्पना है। एअर इंडिया एसएटीएस द्वारा संचालित मल्टी-माडल कार्गो हब, वाईईआईडीए सेक्टर-10 में 206 एकड़ का इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 3,706 करोड़ रुपये का एचसीएल-फाक्सकान सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम नोएडा से जेवर तक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नए औद्योगिक हब की नसें हैं। वाईईआईडीए की एफडीआई और फार्च्यून-500 नीति के तहत अब तक आठ कंपनियों ने इस गलियारे में लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

सेमीकंडक्टर संयंत्र का महत्व विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। यहां बनने वाली चिप मोबाइल फोन, लैपटाप और आटोमोबाइल को संचालित करेंगी, वही उत्पाद जो वैश्विक चीन-प्लस-वन आपूर्ति शृंखला पुनर्संरेखण के केंद्र में हैं। नोएडा में सैमसंग का विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्र, हैवेल्स, अंबर एंटरप्राइजेज, माइक्रोसाफ्ट और एचसीएल-फाक्सकान की उपस्थिति से यह गलियारा उत्तर भारत में चीन-प्लस-वन रणनीति का प्राथमिक केंद्र बन चुका है। कार्गो हब का लक्ष्य है कि भारत को, विशेषकर उसके उत्तरी क्षेत्र को, वैश्विक लाजिस्टिक्स का प्रमुख प्रवेशद्वार और चीन-प्लस-वन रणनीति का विश्वसनीय विकल्प बनाया जाए। भारत के पहले एकीकृत एमआरओ केंद्र के रूप में भी जेवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। दशकों से भारतीय एयरलाइंस विमानों के रखरखाव के लिए सिंगापुर और दुबई पर निर्भर रही हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के लोग इन सेवाओं के लिए जेवर आएंगे। जेवर कृषि के लिए भी उतना ही क्रांतिकारी है। फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद और सजावटी फूल अब सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे। इससे किसानों की आय में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर जेवर मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन और राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स नीति तीनों को एक साथ गति देता है। 50,000 प्रत्यक्ष और 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार, फिल्म सिटी, खिलौना पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेंटर का पूरा इकोसिस्टम आज उत्तर प्रदेश और एनसीआर को एक नई वैश्विक पहचान दे रहा है। जेवर हवाई अड्डा एक दिन में नहीं बना है, यह अथक भूमि अधिग्रहण, नीतिगत नवाचार, निवेशक कूटनीति और दूरदर्शी राजनीतिक साहस का सम्मिलित परिणाम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब शासन की बागडोर संभाली थी तब उत्तर प्रदेश देश के तीन सबसे पिछड़े राज्यों में था। अजब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश भी एक लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लेता है। और इतिहास साक्षी है कि-जब उड़ान पट्टी तैयार होती है, तो स्वप्न भी उड़ान भरते हैं।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

एल नीनो की चुनौती और पानी बचाने का संकल्प

डॉ. राजभूषण चौधरी

आज, धरती का पर्यावरण एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ कुदरत के संकेत तेज़ी से साफ़ हो रहे हैं और मौसमों का पारंपरिक चक्र बुरी तरह प्रभावित होता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूर की सोच से मई के आखिर में ही साफ़ इशारा कर दिया था कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। उन्होंने सभी देशवासियों से भरपूर पानी पीने और पानी के सोर्स बचाने के प्रति सचेत रहने की भावुक अपील की थी। प्रधानमंत्री की यह अपील आज के पहले कभी न हुए पर्यावरण संकट के बीच देश को एक सुरक्षित रास्ता दिखाने वाली एक राह दिखाने वाली रोशनी साबित हो रही है।

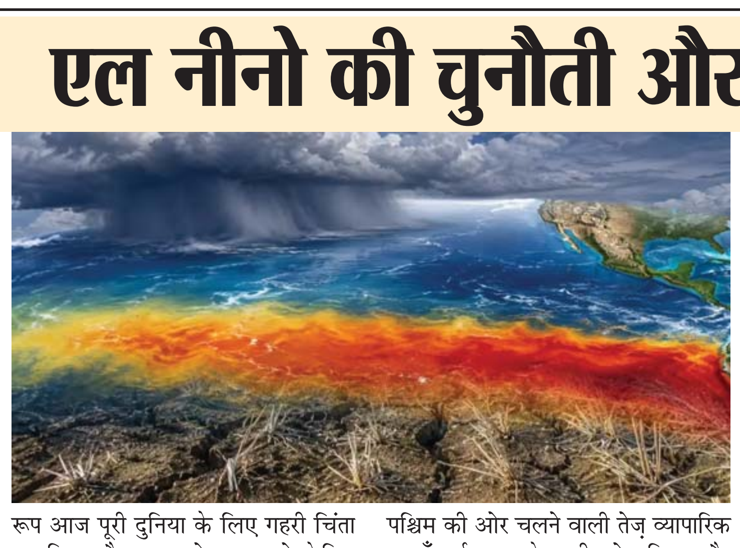

धरती का लगातार बढ़ता तापमान और मौसमी चक्रों में भारी उतार-चढ़ाव इस बात का साफ़ सबूत है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ़ दूर की बात नहीं रह गई है। बल्कि, यह हमारे समय की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल चुनौती बन गई है। बेमौसम भारी बारिश, लंबे समय तक सूखा और गर्मी के मौसम का भयंकर रूप आज पूरी दुनिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। इस ग्लोबल एटमोस्फेरिक उथल-पुथल के केंद्र में प्रशांत महासागर से शुरू होने वाली एक बहुत ही जटिल हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल घटना है, जिसे मॉडर्न साइंस की भाषा में 'एल नीनो' कहा जाता है। भारत जैसे विशाल, घनी आबादी वाले और मुख्य रूप से खेती पर निर्भर देश के लिए, यह एल नीनो साइकिल सिर्फ लैबोरेटरी रिसर्च का विषय नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही गंभीर और प्रैक्टिकल मुद्दा है जो सीधे देश भर के लाखों किसान परिवारों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है।

ओशनोग्राफी के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में, प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली तेज़ व्यापारिक हवाएँ गर्म सतह के पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। इसके असर से दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट से दूर समुद्र की गहराई से ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया ग्लोबल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है और भारतीय मानसून को पॉजिटिव बूस्ट देती है। हालाँकि, एल नीनो इफेक्ट के दौरान, ये व्यापारिक हवाएँ अचानक कमज़ोर हो जाती हैं और कभी-कभी, उनकी दिशा पूरी तरह से उलट भी जाती है। इस वजह से, समुद्र की सतह का गर्म पानी पश्चिम की ओर जाने के बजाय दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाकों की ओर वापस बहने लगता है। समुद्र की सतह का यह असामान्य गर्म होना पूरे एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़ोन को बिगाड़ देता है, जिससे बादल बनने और बारिश की ग्लोबल ज्योग्राफी बदल जाती है। इस घटना से पेरू के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ आती है, वहीं भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिससे मानसूनी हवाओं की रफ़्तार कमज़ोर हो जाती है। भारत के ज़मीनी हिस्से पर इसका सीधा असर बारिश की भारी कमी, बिखरे हुए मानसून और गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के रूप में दिखता है। यह एक साइंटिफिक तबाही है जिसमें देश के पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और पानी के सर्कुलेशन को अस्थिर करने की पूरी क्षमता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बदलते पैटर्न और एल नीनो के असर ने मिलकर देश के लिए पानी के संकट और मौसम की अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है।

प्रधानमंत्री ने हमेशा पानी की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और रक्षा सुरक्षा के बराबर रखा है। उनका साफ मानना है कि पानी बचाना हर नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा और एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए। इसी सोच के आधार पर उन्होंने 'कैच द रेन' कैंपेन शुरू किए, जिसका मूल मंत्र है कि मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करके, हमें बारिश के पानी की हर बूंद को वहीं बचाना चाहिए जहाँ वह धरती पर गिरती है। देश के इतिहास में पहली बार, मौजूदा सरकार ने 'जल शक्ति मंत्रालय' के रूप में एक जुड़ा हुआ और मज़बूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बनाया, जो देश की पानी की प्लानिंग को एक नई, साइंटिफिक और सही दिशा देने में सच में एक बदलाव लाने वाली पहल साबित हुई है। बढ़ते कंक्रीटीकरण और बिना प्लान के इस्तेमाल की वजह से धरती के पानी के लेवल में लगातार हो रही गिरावट को रोकने और पानी के सोर्स की लंबे समय तक सुरक्षा पक्का करने के लिए, सरकार ने पॉलिसी और प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क बनाया है।

देश में 'जल जीवन हरियाली मिशन' ने पर्यावरण संतुलन और पानी बचाने को एक नई तेज़ी दी है। 'जल जीवन मिशन' के ज़रिए आज 'हर घर जल' के संकल्प के साथ देश के हर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाके में शुद्ध, टेस्टेड और लगातार पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, 'अटल भूजल योजना' के तहत, ज़्यादा इस्तेमाल वाले इलाकों में कम्युनिटी की भागीदारी को बढ़ावा देकर साइंटिफिक मैनेजमेंट और ग्राउंड वॉटर लेवल का रिचार्ज किया जा रहा है। खेती के सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए, 'प्रधानमंत्री क्रृषि सिंचाई योजना' के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी मॉडर्न माइक्रो-इरिगेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार की आंख के तारे, करें हरदम वारे-न्यारे

सरकार को सरकाने की सारी जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकार को हवा का पर्यायवाची मानता है, इसलिए जिस तरफ हवा चलती है, उसी तरफ पीठ कर लेता है। सरकार को सरकाने की सारी जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकार को हवा का पर्यायवाची मानता है, इसलिए जिस तरफ हवा चलती है, उसी तरफ पीठ कर लेता है। वायु, वाम-दक्षिण, ऊर्ध्व-अधो... किधर भी चले, वह उसी दिशा में सांस लेता है। कर्मचारी की एक विशेषता यह होती है कि वह सरकार से डरता है। सरकार के विरुद्ध कुछ सुनकर कान बंद कर लेता है। अखबार नहीं पढ़ता क्योंकि उनमें सरकार के खिलाफ भी छपता है। टीवी में वह न्यूज चैनलों को ब्लॉक करके रखता है कि कहीं सरकार देख न ले कि वह सरकार के विरुद्ध समाचारों देख रहा है। वह सरकार का दिया खाता है, इसलिए ईमानदारी से उसे भी निभाता है।

वह व्हाट्सएप समूह में भी जुड़ा है। नियम से गुड मार्निंग के फूल-पत्ती वाले संदेश डालता है। कभी-कभी वह मंत्री जी को माला पहनाते हुए अपनी तस्वीर डालता है। कोई सरकार के खिलाफ संदेश भेजता है तो एडमिन होने के नाते वह उसे डिलीट कर देता है। डिलीट करने से पहले वह बताता, 'यह सरकारी समूह है, इसमें सरकार के खिलाफ लिखना अशोभनीय है। दंडनीय है। अवांछित है... वर्जनीय है... और नहीं क्या-क्या है।' जब कभी उसके अन्य साथी, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वह आंदोलन में सबसे पीछे चेहरा ढांपकर खड़ा होता है। सरकार के खिलाफ नारे वह मन में भी नहीं लगाता।' कहता है, 'सरकार के खिलाफ सारे आंदोलन, इतवार को होने चाहिए।' वह काली पट्टी भी कमीज के भीतर बांधता है। उसका मानना है कि 'जब सब कि तनख्वाह बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी। फिर क्यों सरकार के खिलाफ जाना?'

ऐसे कर्मचारी को सरकार बुलाती, 'अमुक कुमार! अब मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करूंगी। तू आराम से बिना काम किए तनख्वाह उठा। अपना निजी धंधे करते हुए सरकारी नौकरी भी कर। अब तू अपना एक नया संघ बना ले... और मैं जैसा कहूं वैसा मेरा विरोध कर।' उसने तत्काल एक संगठन बनाया, 'सरकार का प्रबलतम विरोधी संगठन'। उसका वह आजीवन अध्यक्ष बन गया। सरकार ने तत्काल उसे मान्यता दी। वह सरकार से लड़ने के नाम पर अपने साथियों से चंदा लेने लगा। आज वह, मंत्री का दर्जा प्राप्त सरकारी कर्मचारी नेता है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाऐं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रमुख खबरें

गंजपारा में 17.50 लाख रुपए से बनाई जाएंगी नालियां व पुलिया

दुर्ग। वार्ड 36 गंजपारा (पुलिस लाइन क्षेत्र) के लोगों को जलभराव और बाधित हो रहे आवागमन से जल्द राहत मिलने जा रही है। बुधवार को महापौर अलका बाघमार ने वार्ड में 17.50 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों में नाली और पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। बांधा तालाब निचली बस्ती एवं जीवन प्लाजा के पीछे, मंदिर से चौहान निवास तक, मोहन बाल मंदिर के आसपास तथा सरदार पटेल स्कूल के सामने नाली एवं पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी, बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से राहत मिलेगी तथा नागरिकों को आवागमन में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। भूमिपूजन के दौरान महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कर नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पुलिया, पेयजल एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में नालियों और पुलियों की आवश्यकता महसूस की गई, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य स्वीकृत कराए गए हैं। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा और स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण तैयार होगा। भूमिपूजन में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, शिव नायक, प्रतिभा सुरेश गुप्ता, अजय शर्मा, कमल नारायण रूंगटा, विजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।

वीबीजीरामजी योजना का शुभारंभ एवं जनजागरूकता कार्यक्रम संपन्न

दुर्ग। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहदी में VB-GRAM योजना के शुभारंभ एवं जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को योजना की जानकारी प्रदान कर उन्हें रोजगार, आजीविका एवं ग्राम विकास से जुड़े अवसरों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में एपीओ द्वारा VB-GRAM योजना के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण तथा समग्र ग्राम विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को योजना से प्राप्त होने वाले लाभों, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला एपीओ, पीओ, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए सामूहिक सहयोग एवं सहभागिता का संकल्प लिया।

निगम आयुक्त का खुर्सीपार क्षेत्र में निरीक्षण, नागरिक समस्याओं के समाधान के निर्देश

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-4 खुर्सीपार क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर निर्माणाधीन विकास कार्यों और नागरिक भीसुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने तथा नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निगम आयुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नाली निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त करने पर जोर दिया, ताकि जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था निगम की प्राथमिकता है। बालाजी नगर में पाइपलाइन कार्य का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान रहवासियों ने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग रखी, निगम आयुक्त जल्द निराकरण हेतु जोन आयुक्त को निर्देशित किये हैं। आवश्यकतानुसार नल (टैब) लगाने कहा गया है, जिससे पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकी जा सके। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद मिनी माता नगर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वहीं वार्ड क्रमांक 42 गौतम नगर में प्रस्तावित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण स्थल का अवलोकन किया। सड़क के जर्जर होने से नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए आयुक्त ने शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निगम का उद्देश्य विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद के जगदीश, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता संजय वर्मा, सहायक अभियंता चंद्रकांत साहू, उप अभियंता बसंत साहू, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, राजस्व निरीक्षक विजेंद्र परिहार सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

एसआर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे सेलीब्रेशन चेयरमैन ने किया चिकित्सकों का सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग के चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज में बुधवार को 'राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे' हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर चेयरमेन संजय तिवारी द्वारा अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और स्टाफ को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी ने मिलकर केक काटा और खुशियां साझा कीं। यह आयोजन समाज में डॉक्टरों के अद्वितीय योगदान, त्याग और सेवा भावना के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया था।

इस मौके पर एसआर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर्स डे के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, डॉक्टर समाज के लिए सेवा, समर्पण और मानवता के प्रतीक हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए उनका सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है।

डॉक्टरों को मिला सम्मान, सेवा का दोहराया संकल्प

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ रंजन सेन गुप्ता कार्डियोलॉजी सर्जन ने कहा कि,आज का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है,आज, 1 जुलाई, डॉ. बी.सी. राय का जन्मदिन है जिसे चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन पूरे अस्पताल परिवार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा पेशा एक परिवार की तरह है. जिसमें सभी मिलकर एक मरीज का इलाज करते है.और आगे भी हम सब मिलकर एक परिवार की तरह कार्य करते रहेंगे। इसी तरह डॉ केके जैन जनरल मेडिसिन ने भी डॉक्टर्स डे पर प्रकाश डालते हुए कहा आज का दिन डॉ. बी.सी. राय की याद में मनाया जाता है कि,किस तरह उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण निःस्वार्थ सेवा दी थी.उन्होंने अपने जीवन के आखरी दिनों में भी अपनी सेवाएं दी उनके इसी सेवाभाव को याद करते हुए हम सब ने डॉक्टर्स डे मनाया।

इनके अलावा कार्यक्रम को डॉं वाई. के. शर्मा जनरल सर्जन व डॉं वनश्री सिन्हा ने भी सम्बोधित करते हुए कहा कि,डॉक्टर्स डे ये भी संदेश देता है कि,जिस तरह डॉक्टर्स को भगवान का दुसरा रुप मानते है.इसलिए डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ में सेवाभाव होना चाहिए जिस तरह डॉ. बी.सी. राय ने अंतिम क्षणों तक सेवा देते रहे उसी तरह हमें भी निःस्वार्थ होकर सेवा देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एस आर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी का आभार व्यक्त भी किया।

कार्यक्रम के दौरान संस्था के मेडीकल सुप्रीटेन्डेन्ट डॉ. रंजन सेन गुप्ता कार्डियोलॉजी सर्जन, डॉ केके जैन जनरल मेडिसिन, डॉ. वाईके. शर्मा जनरल सर्जन, डॉ. वनश्री सिन्हा नेत्र विभाग को एस आर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी के द्वारा स्मृति चिह्न, उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सम्मान की कड़ी में डॉ. दीपा मिश्रा, डॉ. ममता साहू , डॉ. सुमित सोनी, डॉ. बलिराम रॉय, डॉ. अश्वनी शुक्ला इन्हीं के साथ अस्पताल में बेहतर प्रदर्शन करने पर अन्य विभाग से अभिषेक रिछारिया सीनियर अकाउंटेंट, प्रेम चंद्राकर नेत्र विभाग सहायक, प्रियेश मिश्रा, आयुष्मान इंचार्ज, जगजीत नारायण पांडेय मैनेजिंग डायरेक्टर, सहित सीमा बरहरे, तनुजा साहू को भी सम्मानित किया गया।

इस भावुक और सफल आयोजन में डॉक्टरों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के अन्य कर्मचारी व छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों का अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कलेक्टर ने निकायवार पट्टाधारी सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 जुलाई तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के प्रकरणों का परीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा बकेट क्लेम में लंबित किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एग्रीस्टैक बकेट क्लेम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को बकेट क्लेम की विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

कलेक्टर ने समय-सीमा से बाहर लंबित अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। वहीं विवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के मामलों में पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन अथवा फर्द प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर रक्तदान से दिया मानव सेवा का संदेश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस-2026 के अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महान चिकित्सक, शिक्षाविद् एवं समाजसेवी डॉ. बिधान चंद्र रॉय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), दुर्ग शाखा के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया तथा समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

इस अवसर पर चिकित्सकों ने कहा कि चिकित्सा सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने रोगियों को गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील एवं समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प दोहराया। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद्, समाजसेवी तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य चिकित्सकों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा समाज में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है।

इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने डॉ. रॉय के चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए समाज के प्रति चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), दुर्ग शाखा के अध्यक्ष डॉ. रजनीश मल्होत्रा सहित अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान चिकित्सकों के सम्मान में विशेष 'स्कार्फ समारोह' आयोजित किया गया।

संसाधन स्त्रोत केंद्र हेतु स्पीच थैरेपिस्ट और अटेंडेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

दुर्ग। जिले में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण शासकीय पहल की गई है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के दिशा-निर्देशों के परिपालन में, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग द्वारा विकासखण्ड स्तर पर संचालित संसाधन स्त्रोत केन्द्रों के लिए अस्थाई नियुक्तियों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन स्त्रोत केन्द्रों में रिक्त पदों को भरा जाएगा ताकि विशेष बच्चों को आवश्यक थेरेपी और सहायता सुलभ कराई जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत 'स्पीच थैरेपिस्ट' के 01 पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए निश्चित मानदेय 20,833 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र के सुचारू संचालन और बच्चों की देखभाल हेतु 'अटेंडेंट' के 02 अस्थाई पदों पर भी भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 7,000 रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय देय होगा। इच्छुक और योग्य आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निश्चित की गई है। आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा डिजिटल लिंक जारी किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार स्पीच थैरेपिस्ट पद के लिए निर्धारित गूगल लिंक अपना आवेदन सफलता पूर्वक दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं।

जिले में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन का शुभारंभ

ग्रामीणों को 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार, मजदूरी दर बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला पंचायत सभा कक्ष, दुर्ग में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (जी-रामजी) के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से किए गए राष्ट्रीय शुभारंभ के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल तथा विधायक ललित चंद्राकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा, जनपद पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन, जिला पंचायत सदस्य प्रिया साहू, श्रद्धा साहू, नीलम चंद्राकर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सांसद विजय बघेल ने कहा कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, विकसित

भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का कानूनी रूप से गारंटीशुदा मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर 262 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार गारंटीकृत बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन एवं आपदा-निवारण पर विशेष फोकस किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में स्थायी परिसंपत्तियों एवं आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायतों के सतत एवं समग्र विकास को गति मिलेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों का चयन किया जाएगा। सभी कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक (व्हीबी-एनआरआईएस) के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने कहा कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क एवं अन्य आधारभूत अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर बताया गया कि योजना के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों का कोई आधार नहीं है। रोजगार की गारंटी को कम नहीं बल्कि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। सभी विकास कार्यों का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभाओं द्वारा ही किया जाएगा। योजना के लिए प्राथमिक वित्तीय दायित्व पूर्ववत केंद्र सरकार का रहेगा तथा इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन एवं आधारभूत अधोसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

खास-खबर

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना : आवेदन की अंतिम तिथि अब 12 जुलाई तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 12 जुलाई 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित थी। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी एवं प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत विद्यार्थियों की पढ़ाई का शुल्क, छात्रावास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री तथा अन्य आवश्यक खर्च का पूरा वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल ने अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई है। सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने पात्र बच्चों का आवेदन 12 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से करें। इसके अलावा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, श्रमेव जयते ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पर आवेदन कर सकते हैं।

डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रभावी पहल

रायगढ़। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी पहल किए जा रहे है। इसके तहत मौसम पूर्व तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में बड़ी सफलता के बाद वर्ष 2026 में शून्य डेंगू लक्ष्य पर काम जारी है। लार्वा नियंत्रण, फॉगिंग और जनजागरूकता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए अस्पतालों में विशेष डेंगू वार्ड तैयार किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने बताया कि वर्ष 2026 में डेंगू नियंत्रण को पूर्णतः प्रभावी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभागीय प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में जहां 1968 डेंगू प्रकरण दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2025 में यह घटकर मात्र 30 रह गए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी उम्मीद की किरणः सिर्फ एक सप्ताह में बना आयुष्मान कार्ड

रायपुर। शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इसी सुशासन की सोच को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 लगातार साकार कर रही है। मनेंद्रगढ़ निवासी अभिनव द्विवेदी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ एक शिकायत ने महज़ एक सप्ताह में उनकी चिंता को राहत में बदल दिया। काफी समय से आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण अभिनव द्विवेदी शासन की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद कार्ड जारी नहीं होने से वे परेशान थे। अंततः उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई और समाधान की उम्मीद जताई। शिकायत प्राप्त होते ही प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। विभाग ने मामले को प्राथमिकता से लेते हुए आवश्यक परीक्षण एवं कार्रवाई की।

मुख्यमंत्री साय ने किया योग को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और अनुशासित जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में योग आयोग प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार को नई गति देगा तथा योग को गांव-गांव, विद्यालयों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों से भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है। आज विश्व के 176 से अधिक देश 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग और आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सशक्त बनाने के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद एम्स की स्थापना का आग्रह किया गया है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध है, जिससे भविष्य में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर नई प्रतिष्ठा दिलाई है। उन्होंने कहा कि योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। विधायक किरण सिंह देव ने विश्वास व्यक्त किया कि संजय अग्रवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ योग आयोग प्रदेश के प्रत्येक गांव, शहर और परिवार तक योग की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कार्य करेगा। समारोह में कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद लक्ष्मी वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक किरण देव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित आदि लोग उपस्थित थे।

चिकित्सा में आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय संवेदनाएं भी जरूरी है - राज्यपाल डेका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज विमतारा भवन में सिक्ख समाज छत्तीसगढ़ एवं जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी द्वारा आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का महत्व बढ़ा है, लेकिन रोगी के प्रति मानवीय संवेदनाएं, आत्मीय व्यवहार और नैतिक मूल्यों के साथ की गई चिकित्सा ही समाज का विश्वास मजबूत करती है।

राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर का मधुर व्यवहार कई दवाइयों से भी अधिक प्रभावी होता है। मरीज के लिए चिकित्सक भगवान के समान होता है और उसे वास्तविक संतोष तभी मिलता है, जब डॉक्टर स्वयं उसका शारीरिक परीक्षण कर उसकी स्थिति को समझे। उन्होंने कहा कि आधुनिक जांच तकनीकों का अपना महत्व है, लेकिन मरीज का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपचार भी उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फैमिली डॉक्टर अथवा पड़ोस के डॉक्टर की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इस परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे चिकित्सक परिवारों के स्वास्थ्य और विश्वास का महत्वपूर्ण आधार होते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चिकित्सक इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर अनेक रोगों की रोकथाम की जा सकती है।

उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए कहा कि चिकित्सकों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इनका उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। एआई अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है, लेकिन मानव मस्तिष्क की संवेदनशीलता, विवेक और निर्णय क्षमता का कोई विकल्प नहीं हो सकता।

राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को सोचनीय बताते हुए कहा कि नशे की लत से ग्रस्त लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनका उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सिक्ख समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं सेवा कार्यों की सराहना भी की। राज्यपाल ने सिक्ख समाज के कार्यक्रम में समाज के चिकित्सकों तथा जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। विधायक पुरंदर मिश्रा, जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी के अध्यक्ष डॉ. निखिल मोती रामानी, सचिव डॉ. अविनाश तिवारी, सिक्ख समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा, एम्स रायपुर के निदेशक डॉ. अशोक जिंदल, रिम्स के निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार वाधवा, वरिष्ठ चिकित्सक, सिक्ख समाज के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिला कार्यालय में आयोजित मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में राज्य एवं जिला स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके भविष्य के लक्ष्य, करियर की योजनाओं और रुचियों की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनके आत्मविश्वास और ऊँचे सपनों की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण, अनुशासन, निरंतर अध्ययन और कठिन परिश्रम ही सफलता की वास्तविक कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पूरी निष्ठा से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधनों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रसेवा की भावना को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज सम्मानित हुए विद्यार्थी केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का गौरव हैं।

विकसित भारत-जी रामजी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गतिः मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं जनभागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

श्रीकंचनपथ न्यूज

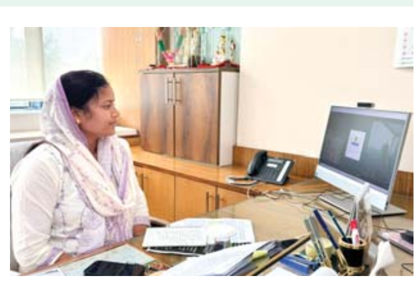

रायपुर। विकसित भारत-जी रामजी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। यह योजना ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार, समयबद्ध भुगतान तथा ग्रामसभा आधारित कार्ययोजनाओं के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह बात महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विकसित भारत-जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर कही।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि विकसित भारत-जी रामजी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आजीविका संवर्धन, आधारभूत संरचना विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी विकसित भारत के निर्माण के प्रमुख आधार हैं तथा इन क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों से ही स्थायी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को पूर्व में उपलब्ध 100 दिनों के रोजगार के स्थान पर अब 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन एवं अनुमोदन किए जाने से विकास कार्यों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि आधारित गतिविधियों तथा टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार होने के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विकसित भारत-जी रामजी योजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं सभी संबंधित विभागों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मार्कफेड मुख्यालय में सहकारी संगोष्ठी का भव्य आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य में मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह (29 जून से 06 जुलाई 2026) के गरिमामयी अनुक्रम में आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के नवा रायपुर स्थित मुख्य कार्यालय में एक दिवसीय 'सहकारी संगोष्ठी' का सफल आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय संगोष्ठी में राज्य के कृषि, खाद्य और सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञों ने शिरकत की।

मार्कफेड के प्रबंध संचालक ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी माननीय मंत्रियों, विशिष्ट अतिथियों और सहकारी संघ के प्रतिनिधियों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी श्गमछाश् पहनाकर और पुष्प गुच्छ से आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने राज्य के किसानों की सेवा में मार्कफेड की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि सहकार से समृद्धि भारत सरकार का प्रमुख दृष्टिकोण और अभियान है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सहकारिता केवल एक नारा नहीं है रह गया है बल्कि यह ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आजीविका को बेहतर बनाने का एक माध्यम बन गई है। चाहे डेयरी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि उत्पादों का विपणन ,सहकारिता इन सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण ला रही है।

श्री द्विवेदी ने कहा कि आज रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जल, वायु, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः इफ्को द्वारा लांच किए गए नैनो उर्वरक का ज्यादा ज्यादा किसानों को उपयोग करना चाहिए वरना आज स्वच्छ पीने के पानी के लिए जिस तरह से बिसलेरी की बोतल लेकर घूमना पड़ता है भविष्य में प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। उन्होंने विपणन संघ के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को साझा किया और विभागीय अधिकारियों को पूरी निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित किया।

संगोष्ठी के मुख्य विषय 'सहकार से समृद्धि' पर विचार रखते हुए अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता प्राथमिक सरकारी समिति ने प्राथमिक सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ब्याज या रियायती दरों पर ऋण वितरण की महत्ता को रेखांकित किया।

श्री कनीराम जी ने सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मनाये जा रहे सहकारी सप्ताह में अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि सहकारिता ही आमजन के मूल में है। सहकारिता से युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं को रोजगार सृजित होंगे। बिन सहकार, नहीं उद्धार के मूल मंत्र को स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से सबको साथ लेकर सही दिशा में काम करने की जरूरत है। राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेललचंदन ने भी सम्बोधित किया।

तकनीकी सत्र में नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. के राज्य प्रतिनिधियों ने कृषक उत्पादक संगठन के गठन, उनके वित्तीय लाभों और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे और सीमांत किसान सामूहिक खेती के जरिए सीधे बड़े बाजारों से जुड़कर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री साय के निर्देशः किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता से मिले खाद-बीज

प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही खेती-किसानी में तेजी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही खेती किसानी का कार्य तेजी के साथ शुरू हो गया है। राज्य में 02 जुलाई की स्थिति में 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 13 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। इस खरीफसीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

प्रदेश के किसानों को अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन खाद और 3.09 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 7.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल आदि की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 13 प्रतिशत है। इस खरीफसीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 02 जुलाई 2026 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 96.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2026 के लिए बीज निगम द्वारा प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 4.30 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 3.09 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो मांग का 62 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में 2.67 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफसीजन में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 13.16 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 7.28 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 47 प्रतिशत है।

अधिकारियों बताया कि राज्य सरकार किसानों को खेती-किसानी में सहूलियते हो इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्प कालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे है। खरीफसीजन 2026 के लिए 30 जून की स्थिति में 5525 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 4517 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया था। इस वर्ष किसानों को 8800 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

जब आयुष्मान के थिएटर ग्रूप ने वामिका गब्बी को कर दिया था रिजेक्ट

एक्ट्रेस ने साझा किया मजेदार किस्सा

आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी हाल ही में रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के साथ 'पति पत्नी और वो 2' में नजर आए थे। पिछले महीने फिल्म प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने आयुष्मान से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया था। जिसमें वामिका ने बताया था कि आयुष्मान खुराना के एक थिएटर ग्रूप ने उन्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया था।

'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी और आयुष्मान खुराना फिल्म की बाकी कास्ट के साथ एक कॉमेडी शो पर पहुंचे थे। जहां बातचीत के दौरान शो में आयुष्मान ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह तब से ही एक्टिंग और सिंगिंग में बहुत ज्यादा शामिल थे।

उन्होंने कहा, 'मेरा एक बैंड और एक थिएटर ग्रूप था, मैं चंडीगढ़ में बहुत मजा कर रहा था।' वामिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए पूछा, 'यह कौन सा थिएटर ग्रूप था? आगाज?' फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उस थिएटर ग्रूप के लिए ऑडिशन दिया था।

वामिका ने कहा, 'उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था।' थोड़ा शर्मिंदा होते हुए आयुष्मान ने जवाब दिया, 'मैं उस समय वहां नहीं था। जरूर मेरे जूनियर्स ने ही आपको रिजेक्ट किया होगा।' वामिका ने तंज कसते हुए कहा, 'हां। लेकिन अब हम साथ में एक फिल्म कर रहे हैं, तो भाड़ में जाओ।' बाद में उन्होंने साफ किया, 'मैं यह बात तुम्हारे जूनियर्स से कह रही हूं, तुमसे नहीं।'

बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं रहा था 'पति पत्नी और वो दो' का प्रदर्शन

'पति पत्नी और वो 2' का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया था। यह फिल्म 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का स्पिरिचुअल सीक्वल थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे।

यह फिल्म मई में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

आयुष्मान और वामिका की पाइपलाइन में हैं कई फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो आयुष्मान और वामिका दोनों के पास कई फिल्में हैं जो जल्द ही आने वाली हैं। आयुष्मान अगली बार आकाश ए. कौशिक की फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आएंगे, जिसमें सारा अली खान भी हैं। इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्मों में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'मुपापा' भी शामिल हैं।

वहीं, वामिका के पास भी कई भाषाओं में कई प्रोजेक्ट्स हैं। वह तमिल फिल्मों 'इरावकालम', 'जिनी' और 'डीसी' में नजर आएंगी। उनकी अगली तेलुगु फिल्म 'G2' है। उनके पास मलयालम और पंजाबी फिल्में 'टिकी टाका' और 'किकली' भी हैं। उनकी आने वाली हिंदी फिल्मों में राजकुमार राव की 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी', 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' और 'कुकु की कुंडली' शामिल हैं।

लड़के मुझे परेशान करते थे, कयादु लोहार ने अपने साथ हुई घटना को किया याद

तमिल एक्ट्रेस कयादु लोहार ने अपने स्कूल के दिनों की एक घटना के बारे में बात की है, जब उन्होंने लड़कों के एक ऐसे ग्रूप का सामना किया था, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें परेशान किया था। अपनी आने वाली तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि शुरू में तो उन्होंने इस परेशानी को नजरअंदाज़ किया, लेकिन आखिरकार उनकी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई।

कयादु ने अपने साथ हुई घटना को किया याद

हाल ही में 'गलाटा तमिल' पॉडकास्ट के एक एपिसोड में कयादु के साथ उनके को-स्टार अथर्व मुरली और प्रीति मुकुंदन भी मौजूद थे। जब उनसे उनके अपने ब्लास्ट मोमेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उस घटना का जिक्र किया। यह सवाल हाल ही में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'ब्लास्ट' में प्रीति के एक्शन सीन के संदर्भ में पूछा गया था।

हालांकि शुरू में वह अपनी कहानी बताने में हिचकिचा रही थीं, लेकिन कायाडू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे लड़कियों को अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला मिलेगा। घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं 10वीं क्लास में थी, तो घर के पास ही क्लास अटेंड करने जाती थी। कुछ लड़के मुझे परेशान करते थे। पहले दिन मैंने सोचा ठीक है, जाने दो। दूसरे दिन भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तीसरे दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई।

गलत को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए

कायादु ने आगे कहा कि मैं इतनी परेशान और गुस्से में थी कि मैंने एक पत्थर उठाया और उनमें से एक पर फेंक दिया। वह पत्थर उसके सिर पर लगा और उससे खून बहने लगा। मैं तुरंत वहां से चली गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि वह बहुत हिंसक हरकत थी।

मुझे नहीं लगता कि किसी को पत्थर उठाकर किसी को घायल करना चाहिए। लेकिन उस पल मुझे ऐसा ही महसूस हुआ और मैंने वही किया। शायद लोग सोचते हों कि मैं शांत हूं और ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन जब कोई कुछ गलत करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। आपको अपने लिए आवाज उठानी चाहिए।

कयादु की पाइपलाइन में हैं कई फिल्में

कयादु को आखिरी बार तेलुगु फिल्म 'फंकी' और मलयालम फिल्म 'पल्लीचट्टम्बी' में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म 'इधयम मुरली' 10 जुलाई को सिनेमाघरों म ` · रिलीज होने वाली है। उनके पास कई फिल्में लाइन में हैं, जिनमें तमिल में 'इम्मोर्टल' और 'मंजनाथ्थी', मलयालम में 'आई एम गेम', 'खलीफा: द इंट्रो' और 'थारम' और तेलुगु में 'द पैराडाइज' शामिल हैं।

फिल्म इश्कनामा से शहनाज गिल की पहली झलक जारी, 24 जुलाई को होगी रिलीज

शहनाज गिल को लोकप्रियता अब सिर्फ पंजाबी फिल्म जगत तक सीमित नहीं रही है। हिंदी पट्टी के दर्शक भी उनके जबरा फैन बन चुके हैं। फिलहाल अभिनेत्री अपनी आगामी फिल्म इश्कनामा को लेकर चर्चा बटोर रही हैं।

सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म से अपनी पहली झलक जारी कर दी है जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। फिल्म के निर्देशन की कमान अरविंदर खैरा ने संभाली है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है।

इश्कनामा के पोस्टर में शहनाज दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपा रखा है। दूसरी तस्वीर में वह जय रंधावा के साथ नजर आ रही हैं, जो फिल्म के अभिनेता हैं। पोस्टर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, मेरी आने वाली फिल्म की पहली तस्वीर इश्कनामा सच्चे प्रेमियों निम्मा-नसिमा की सच्ची कहानी 24 जुलाई, 2026 को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। बता दें, शहनाज को बिग बॉस 13 से लोकप्रियता मिली थी।

कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद? जानें इसके लाभ

कच्चे अंकुरित अनाज को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये न केवल स्वाद में अच्छे होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अंकुरित अनाज में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कच्चे अंकुरित अनाज को खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।

पाचन के लिए है बेहतरीन

कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो मल त्याग को आसान बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज में मौजूद खास तत्व पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इन्हें खाने से पेट साफ रहता है और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है।

वजन को नियंत्रित करने में सहायक

अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी हो सकता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन कैलोरी में कम होते हैं। इसलिए इन्हें खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। अंकुरित अनाज में मौजूद फाइबर चर्बी के अवशोषण को कम करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

दिल की सेहत को बढ़ावा

दिल की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखें। इसके लिए कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल की सेहत में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को स्वस्थ रखते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती

शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी कच्चे अंकुरित अनाज फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें विटामिन-सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को मजबूती देने के साथ-साथ शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लडने की क्षमता भी देते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को दूर करने में भी मदद करते हैं।

मधुमेह के जोखिम में कमी

खून में शक्कर की मात्रा बढने से मधुमेह का खतरा हो सकता है, कच्चे अंकुरित अनाज से इस बीमारी के जोखिम कम किए जा सकते हैं। फाइबर शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इनमें मधुमेह रोधी गुण होते हैं, जो खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन नहीं, उसे सही तरीके से पकाना भी है जरूरी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन खाने से ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पकाने पर भी निर्भर करता है। स्मार्ट कुकिंग की आदतें अपनाकर हम भोजन को अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं।

खाना पकाते समय छोटी-छोटी सावधानियां लंबे समय तक हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि खाना बनाते समय तेल की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग बिना माप के तेल डाल देते हैं, जिससे भोजन में आवश्यकता से अधिक वसा शामिल हो जाती है। इसलिए, तेल डालने के लिए हमेशा चम्मच का उपयोग करना चाहिए। इससे तेल की सही मात्रा का उपयोग होता है और अतिरिक्त कैलोरी से बचाव होता है। कम तेल में बना भोजन हृदय के लिए बेहतर होता है तथा मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के खतरे को भी कम करता है।

दूसरी महत्वपूर्ण आदत है बार-बार तला हुआ भोजन खाने से बचना। तले हुए खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनमें अधिक मात्रा में वसा और कैलोरी होती है। नियमित रूप से समोसा, पकौड़े, चिप्स, पूड़ी या अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। यदि कभी तला हुआ भोजन खाना भी हो, तो उसे सीमित मात्रा में और कभी-कभार ही खाना चाहिए। दैनिक भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को अधिक स्थान देना चाहिए।

स्वस्थ जीवन के लिए खाना पकाने के तरीकों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीजों को तेल में तलने के बजाय भाप में पकाना, भूनना, उबालना या ग्रिल करना अधिक लाभदायक होता है। भाप में पकी सब्जियों में विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में सुरक्षित रहते हैं। ग्रिल या रोस्ट किए गए खाद्य पदार्थ कम तेल में तैयार हो जाते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार हल्का भूनकर या उबालकर बनाया गया भोजन पाचन के लिए भी बेहतर माना जाता है।

इसके अलावा, ताजी सामग्री का उपयोग करना, भोजन को अधिक देर तक न पकाना और आवश्यकता से अधिक नमक तथा चीनी का प्रयोग न करना भी स्मार्ट कुकिंग का हिस्सा है। घर का ताजा बना भोजन हमेशा बाहर के जंक फूड की तुलना में अधिक सुरक्षित और पौष्टिक होता है।

खास खबर

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्राम योजना का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्राम योजना' का शुभारंभ किया गया। सुकमा जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम किसान हितग्राहियों के एग्रीस्टैक पंजीयन में हासिल किया प्रथम स्थान

बेमेतरा । जिले में किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। एग्रीस्टैक परियोजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के पंजीयन में बेमेतरा जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारी समितियों तथा मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। जिले में एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत किसानों के पंजीयन का कार्य निरंतर गति से किया जा रहा है। अब तक 1 लाख 70 हजार से अधिक कृषकों का सफलतापूर्वक एग्रीस्टैक पंजीयन कर उनकी किसान आईडी तैयार की जा चुकी है। जिले में कुल कृषकों की संख्या लगभग 1.86 लाख है।

कृषि महाविद्यालय कुरूद के विद्यार्थियों ने रचा नया कीर्तिमान

धमतरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद के विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट एवं उद्योग-संस्थान सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर महाविद्यालय एवं जिले का गौरव बढ़ाया है। अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा के सतत् मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा उद्योगों के साथ प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कृषि बीज कंपनी, कोलकाता में हुआ है। कंपनी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के उपरांत महाविद्यालय के छात्र कमल कुमार, विकास कुमार, हिमांशी चंद्राकर एवं गौरव कुमार साहू का चयन रायपुर स्थित कंपनी के प्लांट में दो माह की इंटर्नशिप के लिए किया गया है। इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को 7 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के साथ नि:शुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पुल निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा

कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण कर हर महीने प्रगति की समीक्षा के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, मैदानी अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर प्रदेश में निर्माणाधीन पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिरपुर भवन स्थित सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण कर हर महीने प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार हर कार्य की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने राज्य में निर्माणाधीन सभी पुलों की प्रगति की संभागवार और वर्षवार समीक्षा की। उन्होंने बस्तर में आरसीपीएलडब्लूए के अंतर्गत प्रगतिरत पुलों के कार्य हर हाल में दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के निर्माण के लिए प्रत्येक चरण और प्रक्रिया को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता को एसओपी बनाने को कहा। उन्होंने इनका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित करने को कहा।

विभागीय सचिव ने पुलों के निर्माण के दौरान कार्यस्थलों पर सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा ध्यान रखने को कहा, जिससे की जान-माल की कोई हानि न हो। उन्होंने पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के निर्माण में सड़क सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को फील्ड में कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को हर महीने भुगतान करने को कहा।

श्री बंसल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए कार्यों की प्राथमिकता तय कर उनके प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पहुंचविहीन गांवों तक बारहमासी कनेक्टीविटी के लिए पुलों के प्रस्ताव के साथ ही द्रुतगामी सड़कों में भी जहां पुलों की जरूरत है, उनके भी प्रस्ताव प्राथमिकता सूची में शामिल कर भेजने को कहा।

उन्होंने कलेक्टरों के साथ समन्वय कर ब्लॉस्टिंग की अनुमति, भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन, पेड़ कटाई तथा स्थल विवाद के लंबित मामलों का तेजी से निराकरण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इनका निराकरण नहीं होने की स्थिति में उच्च कार्यालयों को अवगत कराने को कहा, ताकि उच्च स्तर पर इनका समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही से काम करते हुए निर्माण सामग्री और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में पुलों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सभी पुलों की जानकारी 10 जुलाई तक अपलोड करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी और अधीक्षण अभियंता डी.के. माहेश्वरी सहित सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंता, सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता तथा सभी उप संभागों के अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव बंसल ने पुलों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य एवं कार्यस्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली।

उन्होंने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्णता में कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, लोगों के बारहमासी आवागमन और माल परिवहन की दृष्टि से पुलों के निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हैं।

स्काई-वॉक के संचालन-संधारण की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

श्री बंसल ने रायपुर में निर्माणाधीन स्काई-वॉक के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके संचालन और संधारण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके चालू होने के बाद साफ-सफाई, रखरखाव और बिजली आपूर्ति की स्थायी और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने इसके हैंड-ओवर के लिए नगर निगम से चर्चा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्काई-वॉक का काम इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। लोगों के चढ़ने-उतरने के लिए 1.2 किमी लंबाई के इस स्काई-वॉक में 9 एस्केलेटर्स और 4 लिफ्ट भी लगाए जाएंगे।

श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन में असंख्य श्रमिकों को मिला तत्काल लाभ

शिविर में लोगों ने स्वास्थ्य जांच, नवीन श्रम कार्ड पंजीयन और ईंकेवायसी कराया

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन का जिला स्तरीय आयोजन मंडी प्रांगण सारंगढ़ में किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रमिकों ने नवीन श्रम कार्ड और ईकेवायसी करवाया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली।सम्मेलन में श्रम विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने- अपने स्टॉल लगाए गए थे।

श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा श्रम पंजीयन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि यह सम्मेलन पूरी तरह श्रमिकों को समर्पित है। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ और जानकारी उपलब्ध कराकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

सम्मेलन में श्रमिक ईश्वर पटेल ने बताया कि उनकी संतान अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। वहीं हितग्राही चौतराम विश्वकर्मा की पुत्री ने भी योजना के तहत कक्षा 7वीं में नि:शुल्क अध्ययन करने का अनुभव साझा करते हुए शासन एवं श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 10 हितग्राहियों को कुल 10 लाख रुपये, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 12 हितग्राहियों को 2.40 लाख रुपये, मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत 32 हितग्राहियों को 6.40 लाख रुपये, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 6 हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,618 हितग्राहियों को 32.47 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के श्रमिक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत बर्मन, एसडीएम वर्षा बंसल, गणमान्य नागरिक ज्योति लाल पटेल, जगन्नाथ केशरवानी, श्रम अधिकारी घनश्याम पाणीग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

पीएम जनमन योजना ने बदली सरजू कोरवा के परिवार की जिंदगी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रही है।

योजना के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का नया अध्याय जुड़ रहा है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजना से लाभान्वित परिवार अब कच्चे और असुरक्षित आवासों से निकलकर पक्के घरों में सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। आवास के साथ-साथ उन्हें शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत चिलमा निवासी सरजू कोरवा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास मिलने से सपरिवार सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। श्री सरजू कोरवा पहले अपने परिवार के साथ मिट्टी के छप्पर वाले कच्चे मकान में निवासरत थे।

बरसात के मौसम में लगातार पानी टपकता था, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पीएम जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृत होने, समय पर भुगतान एवं तकनीकी मार्गदर्शन मिलने से उनका पक्का मकान निर्धारित समय में पूर्ण हो सका।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिए निर्देशः किसानों तक हर योजना का लाभ पहुंचे, बढ़े आय और उत्पादन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने गुरुवार को बीजापुर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में संचालित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों की आय में वृद्धि तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए नलकूप एवं कूप निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने तिलहन, दलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, हल्दी एवं गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास करने पर बल दिया। बैठक में पार्लर प्रोजेक्ट के तहत हल्दी की खेती, नारियल एवं ऑयल पाम के पौधारोपण तथा उद्यानिकी विभाग के लक्ष्यों की भी समीक्षा की गई। बीजापुर जिले में मक्का उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना करते हुए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान विभागीय भूमि के बेहतर उपयोग, रबी फसलों विशेषकर गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, बीज उत्पादन कार्यक्रम, जैविक खेती तथा दलहन-तिलहन मिशन के प्रभावी संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने दंतेवाड़ा जिले में पिछले सात वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित जैविक खेती मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को जोड़ने, सभी किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पात्र किसानों तक भी शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पशुधन पोर्टल, टीकाकरण, मोबाइल वेटनरी यूनिट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बकरी पालन, सूकर पालन एवं उन्नत मादा पालन योजनाओं की प्रगति का परीक्षण किया गया। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में हैचरी विस्तार, मछली एवं झींगा पालन को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड, एनएफडीपी पंजीयन तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

जशपुर में जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, समस्याएं और सुझाव सुने

जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रतिबद्धः डॉ. आशा लकड़ा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों के साथ संवाद किया। बैठक में उन्होंने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, शिकायतों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि सभी वैध मामलों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में विधायक गोमती साय एवं रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय तथा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मूल उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें न्याय दिलाना तथा उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आयोग का छत्तीसगढ़ प्रवास जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग केवल शिकायतों की सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा भी करता है। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो पाता, उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

डॉ. लकड़ा ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनके संघर्ष ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक आधार तैयार किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय, शोषण या अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं, तो आयोग ऐसे मामलों में गंभीरता से सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

उन्होंने बताया कि देश में लगभग 12 करोड़ अनुसूचित जनजाति के नागरिक और 725 से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। इनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए वर्ष 2004 में संविधान के अनुच्छेद 338(क) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। आयोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों के क्रियान्वयन की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा कर सरकार को आवश्यक सुझाव देता है।

डॉ. लकड़ा ने कहा कि आयोग को जांच के दौरान दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग आवश्यक होने पर किसी भी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, सार्वजनिक अभिलेख तलब कर सकता है तथा प्रकरणों की विधिवत सुनवाई कर सकता है। आयोग की अनुशंसाएं कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कंसल्टेंट एच.आर. मीणा एवं जे.पी. सिंह, आयुक्त संजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

डॉ. आशा लकड़ा ने जनजातीय समुदाय से अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आयोग के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को डायरी नंबर जारी किया जाता है, जिसके आधार पर प्रकरण की सुनवाई की जाती है। उन्होंने आवेदन करते समय पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं पिनकोड सही ढंग से दर्ज करने की अपील की।

वन प्रबंधन समितियां को मत्स्य पालन से बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

रायपुर। तालाब निर्माण से मिला रोजगार, 400 किलो मछली उत्पादन से लगभग 80 हजार रुपए की आयमुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और वन प्रबंधन समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा वनमंडल के गीदम परिक्षेत्र की कासोली वन प्रबंधन समिति ने मत्स्य पालन के माध्यम से आय बढ़ाने की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कासोली ग्राम के कक्ष क्रमांक 1338 में तालाब का निर्माण किया गया।

खास खबर

रिश्वत लेते बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार

दुर्ग। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसने अपने ही विभाग के बाबू पीएफ की राशि जारी करने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक, विद्युत यांत्रिकी विभाग में कार्यरत एक बाबू ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने पीएफ से 5 लाख निकालने का आवेदन दिया था। आरोप है कि राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में सहायक ग्रेड 2 शिव कुमार ठाकुर ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत बाबू ने एसीबी से कर दी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सहायक ग्रेड 2 शिव कुमार ठाकुर को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

बलरामपुर में बिजली गिरने से मां-बेटी की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब तेज होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। इसके असर से प्रदेशभर में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने के आसार है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच बलरामपुर जिले में बिजली गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई है। मानती टेकाम (33) और उनकी बेटी कुमारी विमला टेकाम (14) खेत में काम करने गई थीं। गुरुवार दोपहर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों खेत के पास स्थित पेड़ के नीचे खड़ी थीं, तभी चपेट में आ गईं। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश हुई है। राजपुर में तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे-343 के किनारे स्थित कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया। घरों में रखा अनाज, बिस्तर, कपड़े, फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान भीग गए।

सट्टे पर पुलिस का शिकंजा, दो सटोरिये रंगे हाथ गिरफ्तार

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, सट्टा और मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना बसंतपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बंगाली चाल स्थित सोनू पान ठेला के पास दो व्यक्ति रुपये का दांव लगवाकर सट्टा-पट्टी लिख रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को सट्टा-पट्टी लिखते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष यादव उर्फ सोनू और रविन्द्र कुमार साहू उर्फ जू है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,700 रुपये नकद, दो सट्टा-पट्टी, दो डॉट पेन और एक वीवो मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया।

300 से ज्यादा होटलों में ठगी करने वाला जॉन गिरफ्तार

चार्ल्स शोभराज से था प्रभावित, वेटर की नौकरी का पैसा नहीं मिला तो बना ठग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। देशभर के 5 स्टार होटलों को निशाना बनाकर ठगी और चोरी करने वाले अंतरराज्यीय ठग बिंगसन जॉन को रायपुर पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 से ज्यादा राज्यों के करीब 300 होटलों में ठगी और चोरी करने का आरोप है।

शुरुआती दिनों में वह एक होटल में वेटर था, लेकिन बाद में फर्जी पहचान के सहारे महंगे होटलों में ठहरकर वारदातें करने लगा। जांच में यह भी सामने आया कि वह कुख्यात ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था।

रायपुर के तेलीबांधा स्थित हयात होटल में भी आरोपी 27 जून को 63,755 का बिल चुकाए बिना फरार हो गया था। वह होटल से करीब 1.48 लाख का किराए का लैपटॉप भी लेकर भाग गया था। होटल प्रबंधन की शिकायत पर जांच शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के भीतर उसे भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लैपटॉप बरामद कर लिया। मामला तेलीबांधा स्थित होटल हयात का है। होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज सूरज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 25 जून को होटल में ठहरा था। 27 जून की सुबह वह बिना चेक-आउट किए होटल से भाग गया।

उसने होटल का 63,755 रुपए का बिल भी नहीं चुकाया। इतना ही नहीं उसने अपनी मांग पर किराए पर लिया गया करीब 1.48 लाख रुपए का लैपटॉप भी साथ ले गया। बाद में होटल प्रबंधन ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले।

शिकायत मिलने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान होटल में जमा दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच की गई।

इससे आरोपी की लोकेशन ओडिशा के भुवनेश्वर में मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची और घटना के महज 72 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से होटल का लैपटॉप भी बरामद कर लिया है।

300 से ज्यादा 5 स्टार होटलों को बना चुका है निशाना

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1990 से अब तक वह देशभर के 300 से अधिक 5 स्टार होटलों में ठगी और चोरी की वारदात कर चुका है। पुलिस के अनुसार वह पहली बार साल 1996 में तिहाड़ जेल गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कुख्यात ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था। इसी वजह से उसने लोगों को धोखा देने के नए-नए तरीके अपनाए। आरोपी खुद को कभी विदेशी ट्रैवल गाइड, कभी इंग्लिश टीचर तो कभी योगा टीचर बताकर महंगे होटलों में ठहरता था। कई दिनों तक होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता और फिर बिना बिल चुकाए होटल का सामान लेकर फरार हो जाता था।

तमिलनाडु का रहने वाला है आरोपी

बिंगसन जॉन मूल रूप से तमिलनाडु के तूतीकोरिन का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह अब तक देश के अलग-अलग राज्यों की जेलों में करीब 15 साल बिता चुका है। रायपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, अब पुलिस दूसरे राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज मामलों का रिकॉर्ड भी जुटा रही है।

रायपुर में ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्तीः एक रात में 39 चालक पकड़े गए, अब तक 3633 पर कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस का ड्रंक एंड ड्राइव अभियान लगातार जारी है। बुधवार रात चलाए गए अभियान के दौरान 39 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के मुताबिक, इस वर्ष अब तक नशे में वाहन चलाने वाले 3,633 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

सहायक पुलिस आयुक्त की मॉनीटरिंग पर एक्शन

यातायात पुलिस ने 1 जुलाई की रात सहायक पुलिस आयुक्त सतीश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में शहर के नौ प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान आधुनिक ब्रीथ एनालाइजर मशीनों से वाहन चालकों की जांच की गई। जांच में 27 कार चालक, 3 पिकअप चालक, 7 ट्रक-मेटाडोर चालक और 2 दोपहिया चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले। सभी वाहनों को रोककर नियमानुसार चालानी और वैधानिक कार्रवाई की गई।

शराब पीकर गाड़ी ना चलाने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन बिल्कुल न चलाएं। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी या परिवार के किसी सदस्य की मदद लें।

यातायात नियमों का पालन कर न केवल अपनी, बल्कि अन्य लोगों की जान भी सुरक्षित रखी जा सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गांजा-प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 16 लाख का नशीला सामान जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 किलोग्राम गांजा, 2,000 प्रतिबंधित नाइट्रोटेन टैबलेट, 30 बोतल कोडिन सिरप, 290 पेंटाजोसीन इंजेक्शन, 300 सिरिंज और नकदी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, जब्त मादक पदार्थ और अन्य सामग्री की कुल कीमत लगभग 10.70 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुल 16.15 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और अन्य सामान जब्त किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 30 जून को गंज थाना क्षेत्र से 10.710 किलो गांजा के साथ मेरठ निवासी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि गांजा ओडिशा से लाकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।

इसके बाद उसके बयान के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गंज थाना पुलिस ने गिरोह के बैकवर्ड लिंक की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के अन्य सदस्य रायपुर आने वाले हैं।

सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पुलिस ने ओडिशा निवासी किशोर साहू, महासमुंद निवासी अजय विश्वकर्मा, शुभम साहू उर्फ बऊ, और मेरठ निवासी प्रिंस प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके बैग से गांजा, प्रतिबंधित दवाइयां, इंजेक्शन, कोडिन सिरप और सिरिंज बरामद किए गए।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह का मुख्य आरोपी किशोर साहू पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उसे महासमुंद की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, वह फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर था और दोबारा नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय हो गया था।

नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, यह अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय है। मामले में सप्लायर, रिसीवर और पूरे नेटवर्क की एंड-टू-एंड जांच की जा रही है। साथ ही जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की अन्य प्रासंगिक धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है।

मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 19.50 लाख की ठगी, 2 आरोपी अरेस्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा करते हुए केरल के पलक्कड़ जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर बचेली निवासी एक शख्स से 19.50 लाख रुपए की ठगी की थी।

मामले में बचेली थाना में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान साइबर सेल ने बैंक लेनदेन और पैसों के ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की। साइबर फॉरेंसिक टूल्स की मदद से यह पता लगाया गया कि ठगी की रकम कहां-कहां भेजी गई। इसके बाद निरीक्षक मधुनाथ ध्रुव सहित संयुक्त टीम को 16 जून 2026 को केरल भेजा गया।

लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से पलक्कड़ जिले के पट्टाम्बी थाना क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बैंक खातों को किराए पर लेकर साइबर ठगी की रकम को उन खातों के माध्यम से इधर-उधर ट्रांसफर करते थे।

इसके बाद रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर जांच एजेंसियों से बचने और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने का प्रयास किया जाता था। पुलिस जांच में आरोपियों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सहित 9 राज्यों में कुल 17 साइबर शिकायतें दर्ज होना भी सामने आया है।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहम्मद अंसार (22) और पी.यू. मोहम्मद रूशीद (22) है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक तथा नगद राशि जब्त की है।

पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील

दंतेवाड़ा पुलिस ने आमजन से अपील की गई है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल अरेस्ट अथवा किसी अन्य बहाने से यदि कोई व्यक्ति धनराशि की मांग करता है तो उसके झांसे में न आएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज साझा न करें। यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा निकटतम पुलिस थाना से संपर्क करें।

महिला से लूट, स्कूटी सवार बदमाश ने पर्स छीना, जेवर-कैश लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी के सरोना इलाके में बुधवार सुबह स्कूटी सवार बदमाश ने पैदल जा रही महिला का पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पर्स में करीब 2.60 लाख रुपए के सोने के जेवर, मोबाइल फोन और नकदी रखी थी। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। पीड़िता का नाम चंद्रिका देवांगन बताया जा रहा है। डीडी नगर पुलिस के अनुसार कवर्धा जिले के देवांगन पारा की गृहिणी चंद्रिका देवांगन अपने पति अशोक कुमार देवांगन के साथ सरोना स्थित अपनी बेटी के घर नातिन के बर्थडे में शामिल होने आई थी। कार्यक्रम के बाद बुधवार सुबह दोनों पति-पत्नी वापस कवर्धा लौटने के लिए पैदल सरोना चौक की ओर जा रहे थे।

सुबह करीब 6 बजे जब वे राधाकृष्ण मंदिर के पास पहुंचे, तभी सामने से स्कूटी पर आए एक युवक ने महिला के कंधे पर टंगा पर्स झपट लिया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि दंपती संभल भी नहीं सके। आरोपी पर्स लेकर केपीएस स्कूल की ओर फरार हो गया। हड़बड़ी के कारण पीड़ित दंपती स्कूटी का नंबर भी नहीं देख सके। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पर्स में एक सोने का रानी हार, एक सोने की चेन, एक जोड़ी सोने के ईयररिंग, करीब एक हजार रुपए नकद और रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन रखा था। चोरी गए जेवरों की कीमत लगभग 2.50 लाख रुपए बताई गई है।

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बिना ड्राइवर चली गाड़ी, रोकने के प्रयास में ड्राइवर की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की पहियों के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची बालको पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, ट्रेलरमानिकपुर खदान से कोयला लेकर बालको प्लांट पहुंचा था। दोपहर करीब 1 बजे चालक संतोष कुमार खैरवार (47), निवासी कोरबा, रिंग रोड स्थित शर्मा पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर खड़ा कर नीचे उतरा।

ट्रेल रोकने की कोशिश में हुआ हादसा

इसी दौरान ट्रेलर अचानक बिना चालक के आगे बढ़ने लगा। वाहन को आगे बढ़ता देख संतोष कुमार उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ने से वह सीधे ट्रेलर के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चश्मदीदों ने बताई हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ड्राइवर ने ट्रेलर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वाहन पर नियंत्रण नहीं हो सका। ब्रेक नहीं लगने और सड़क पर फिसलन के कारण वह हादसे का शिकार हो गया।

घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

रिंग रोड पर लगातार हो रहे हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि बालको रिंग रोड पर कोयला परिवहन करने वाले ट्रेलर, डंपर और हाइवा की लगातार आवाजाही रहती है। भारी वाहनों के दबाव के बावजूद यहां प्रभावी ट्रैफिक नियंत्रण और गति पर निगरानी नहीं होने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

यह पिछले पांच दिनों में रिंग रोड पर दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले तेज रफ्तार भारी वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सीएम साय के निर्देश पर अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा सख्त और सतत अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है तथा नियमानुसार अर्थदंड एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन का उद्देश्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना है। सरकार

इसी क्रम में राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 52 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। इनमें अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 तथा भंडारण के 2 प्रकरण शामिल हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया तथा मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन (पीसी-130-7) मशीन को जब्त कर सील किया गया। संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

बलरामपुर जिले में खनिज विभाग ने राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक टिपर जब्त किया। वहीं बसंतपुर स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत भी जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया। सरगुजा जिले में शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में प्रयुक्त जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है। संशोधित नियमों के अनुसार अब शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो अधिक होगा, के आधार पर वसूला जाएगा।

इसके अतिरिक्त खनिज का बाजार मूल्य भी वसूला जाएगा। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'चेतना विरुद्ध नशा' अभियान के तहत सीपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में 2 जुलाई 2026 को सीपत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भिल्मी में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी शेखर वर्मा (22 वर्ष), निवासी ग्राम भिल्मी, थाना सीपत, जिला बिलासपुर के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई।

मानवता, सेवा और संवेदना का जीवंत केंद्र है सोठी आश्रमः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम में सेवा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास कार्यों का किया अवलोकन, सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जांजगीर-चांपा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान सोठी स्थित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम पहुँचे। आश्रम आगमन पर संस्था के पदाधिकारियों एवं आश्रमवासियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आश्रम प्रमुख सुधीर देव से संस्था की सेवा गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं तथा पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम केवल एक सेवा संस्थान नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और समर्पण का जीवंत केंद्र है। यहाँ वर्षों से समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद लोगों की गरिमा के साथ सेवा की जा रही है।

जो भारतीय संस्कृति के श्नर सेवा ही नारायण सेवाश् के आदर्श को साकार करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान समाज में संवेदनशीलता, सेवा और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने संस्था के संस्थापक स्वर्गीय सदाशिव गोविंद कात्रे के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके सेवा भाव को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम के लिए नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस आश्रमवासियों एवं जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने आश्रम परिसर का भ्रमण कर सेवा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने आश्रमवासियों से आत्मीय भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें उपहार भी भेंट किए। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौमाता की पूजा-अर्चना कर हरा चारा अर्पित किया और गौसेवा का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित संत गुरु घासीदास चिकित्सालय का निरीक्षण कर ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, बिलिंग कक्ष, एक्स-रे कक्ष, आईसीयू तथा ऑपरेशन थियेटर सहित विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने पर बल दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने धनवंतरी जनकल्याण समिति सोसायटी, रायपुर द्वारा संचालित निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव वाहन का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाहन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचाई जा रही कैंसर जांच सेवाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि समय पर जांच और उपचार गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा ऐसी पहल जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब,सांसद कमलेश देवी जांगड़े, विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री भोजराज देवांगन, आश्रम के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने बम्हनीडीह के विकास की नई यात्रा का किया शुभारंभ

हसदेव नदी पर पुल, बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय और सर्वसुविधायुक्त मंगल भवन की घोषणा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी है और नगर पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम हैं। नवगठित नगर पंचायत बम्हनीडीह के प्रथम जनप्रतिनिधियों के कंधों पर केवल एक नगर के विकास की नहीं, बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति और जनविश्वास की नींव रखने की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डडसेना एवं सभी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें दायित्व सौंपा है, उसका प्रतिफल पारदर्शी प्रशासन, संवेदनशील कार्यशैली और विकास के रूप में दिखाई देना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बम्हनीडीह के विकास को नई गति देने वाली तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए दहिदा-बम्हनीडीह के बीच हसदेव नदी पर पुल निर्माण, बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय तथा सर्वसुविधायुक्त मंगल भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधासंपन्न बनाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विकास को नई गति देते हुए हर वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर, किसानों को उनकी उपज का सम्मानजनक मूल्य, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए आर्थिक संबल तथा युवाओं के लिए रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल बड़े शहरों के विकास से नहीं, बल्कि बम्हनीडीह जैसे उभरते नगरों को सशक्त बनाने से होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर नागरिक सेवाओं और सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बम्हनीडीह नगर पंचायत जनभागीदारी, सुशासन और विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगी तथा आने वाले वर्षों में क्षेत्र की नई पहचान बनेगी। समारोह में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक किरण सिंह देव ने भी जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, नारायण चंदेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

विशेष लोक अदालत का आयोजन 21, 22 एवं 23 अगस्त को

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय को सरल एवं सुलभ तरीके से घर-घर तक पहुँचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ किया जा रहा है। जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी। विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 तथा 23 अगस्त को होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को शामिल किया जाएगा। विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जाएगा। पक्षकार इन सुलह-प्रयास हेतु बैठकों, वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी रूप से शामिल हो सकते हैं। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। अधिवक्तागण, वादकारियों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

21 अप्रैल को हुए समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। इन सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया गया।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि को आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के आय बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत कृषि यांत्रिकीकरण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजापुर जिले के ग्राम मांझीगुड़ा में किसान योगेश बांकड़े को उपलब्ध कराए गए आधुनिक कृषि यंत्रों का निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों के कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

योजना के अंतर्गत किसान योगेश बांकड़े के लिए लगभग 35 लाख रूपए मूल्य के आधुनिक कृषि यंत्र स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर 14 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है। लाभार्थी को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल एवं स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे खेती अधिक वैज्ञानिक, समयबद्ध और लाभकारी बन सकेगी।

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, खेती की लागत एवं श्रम में कमी आएगी तथा कम समय में अधिक कार्य कर किसान बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने दिया जा रहा तकनीकी प्रशिक्षण

रायगढ़। जिले में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, खाद निर्माण की जानकारी, पीजीएस प्रमाणीकरण, शैक्षणिक भ्रमण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों को ऐसी खेती की तकनीक सिखा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़े और उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर हो। स्वरूप देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक महीने तक जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में ''खेत बचाओ अभियान'' चलाया गया। इसके तहत 930 किसानों ने 337 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती तथा 1126 किसानों ने 429 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती अपनाने की सहमति दी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का गोंडी एवं हल्बी भाषा में होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर कार्यों में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार,दोनों विभागों के संचालक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री राजवाड़े ने हाल ही में बस्तर संभाग के प्रवास तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से हुई चर्चा के दौरान प्राप्त अनुभवों और सुझावों के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय भाषाओं में संवाद अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से बस्तर संभाग में विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार गोंडी एवं हल्बी भाषा में किए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंच सके।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बस्तर संभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन, पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया।

बैठक में उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी जिलों में नियमित मॉनिटरिंग, सतत निरीक्षण और प्रभावी फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों एवं उनकी माताओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार, पौष्टिक आहार तथा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने दिव्यांगजन एवं वृद्धजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के समयबद्ध वितरण, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा नियमित शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए.उन्होंने सियान गुड़ी (डे-केयर सेंटर) एवं वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक के अंत में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान यह स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ है कि क्षेत्र में विकास और विश्वास का नया वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना तीव्र गति से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर दिखाई दे।

कबीरधाम के गंडईखुर्द से वीबी-जी राम जी योजना का हुआ राज्य स्तरीय शुभारंभ

ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी वीबी-जी राम जी योजना - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की नई गारंटी देने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द से किया गया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर योजना का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से किया। इस दौरान वे वर्चुअल माध्यम से ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह से भी जुड़े रहे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) योजना लागू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब काम के अभाव में बेरोजगार न रहे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना से जहां ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, वहीं गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। चौहान ने कहा कि मजदूरों के पसीने का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की सेवा है।

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) योजना का शुभारंभ हो रहा है और छत्तीसगढ़ में इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ ग्राम पंचायत गंडईखुर्द से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में योजना के तहत पहले कार्य के रूप में ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में शेड निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक गांव और पंचायत का समग्र विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे और रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। इनमें जल संरक्षण से जुड़े 107, ग्रामीण अधोसंरचना के 90, आजीविका संवर्धन के 86 तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित 35 प्रकार के कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब जॉब कार्ड के स्थान पर जीआरजी कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जॉब कार्ड में केवाईसी कराने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत डबरी, चेकडैम, बोल्डर चेकडैम, रिचार्ज पिट, वर्षा जल संचयन, नहर लाइनिंग, ग्रामीण सड़क (धरसा), मुरमीकरण जैसे कार्य कर जल स्तर बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर अटल डिजिटल सेवा केंद्र, मुक्तिधाम में शेड, ग्रामीण अधोसंरचना सहित प्राथमिकता वाले कार्य शुरू करने होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत बाउंड्री वॉल, किचन शेड, शौचालय, सामुदायिक पशु शेड, सोलर एवं स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण चौपाल, हाईमास्ट लाइट, स्व-सहायता समूहों के लिए वर्क शेड, कोल्ड स्टोरेज, खाद एवं खाद्यान्न गोदाम, सामुदायिक आटा चक्की, कृषि प्रसंस्करण केंद्र और हैंडलूम प्रोसेसिंग केंद्र जैसे कार्य भी किए जा सकेंगे। इससे रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा, जब गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेंगे।

इसी उद्देश्य से गांवों को ए, बी और सी श्रेणी में विभाजित कर योजनाबद्ध विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है, जो ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि वे व्यापक सोच के साथ अपने गांवों की विकास कार्ययोजना तैयार करें, ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण के सा बने हैं। इस योजना के तहत मनरेगा में अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा तथा अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

गंडईखुर्द को मिली पहली सौगात, शेड निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत प्रदेश के पहले विकास कार्य के रूप में ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में शेड निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत विकास कार्यों के साथ हो रही है। इस स्वीकृति के साथ ही गंडईखुर्द वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बन गई, जहां विकास कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वृहद स्तर पर हुआ पौधरोपण

पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में ष्एक पेड़ मां के नामष् अभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंडरिया विधायक मती भावना बोहरा सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950